

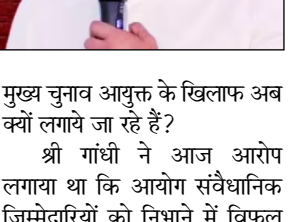
भारत-ब्रिटेन के बीच एफटीए पर हुए हस्ताक्षर द्विपक्षीय कारोबार में 34 अरब डॉलर की होगी वृद्धि

यूँके के बाजार में 5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

अनुमान के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक दोगुना होने की संभावना है, जबकि रत और आभूषण निर्यात अगले तीन वर्षों में दोगुना (वर्तमान 941 मिलियन डॉलर से) होने की संभावना है।

अधिकारियों का अनुमान है कि इस समझौते से लंबी अवधि में भारत को यूँके का निर्यात लगभग 60 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने चेकर्स एस्टेट में स्टारमर से मुलाकात कर विचारों की अपनी चौथी यात्रा पर आधिकारिक कार्यक्रम शुरू किए थे। प्रधानमंत्री मोदी स्टारमर के साथ भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के सर्पण फलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे। बाद में, वह किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे।

चर्चा के दौरान, दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे, जिसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।



नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने कनाटक में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी किए जाने के काँग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और धमकी भरा बताया है।

आयोग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कुछ तथ्यों को सभी भारतवासियों को जानना चाहिए। उसके अनुसार, कनाटक में मतदाता सूची को लेकर काँग्रेस पार्टी द्वारा जमर्तप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक भी अपील दायर नहीं की गयी जो एक वैध कानूनी उपाय था। आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया को लेकर दायर 10 चुनाव याचिकाओं में से एक भी चुनाव याचिका हारने वाले किसी भी क्रिसुप उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की, जबकि वह जमर्तप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत उपलब्ध एक कानूनी उपाय था। आयोग कहा वह यह सोचने पर मजबूर है कि इस प्रकार के आधारहीन और धमकीपूर्ण आरोप

मुख्य चुनाव आवुक्त के खिलाफ अब क्यों लगाये जा रहे हैं?

श्री गांधी ने आज आरोप लगाया था कि आयोग संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है और उसने कनाटक में चुनावी गड़बड़ी होने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग कैसे काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए।

श्री गांधी ने आरोप लगाया, सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब हमारे पास कनाटक में एक सीट पर चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी करने की अनुमति देने से 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि शत-प्रतिशत ठोस सबूत हैं।

श्री गांधी ने कनाटक की एक सीट पर बड़े पैमाने पर मतदाता पंजीकरण में अनियमितता और मतदाताओं का नाम हटायें जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग को संशुद्ध दमा चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं।

सेंट्रल विस्टरा परियोजना का उद्देश्य भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक कुशल और दक्ष केन्द्रीय सचिवालय का निर्माण करना है।

इस समय गृह मंत्रालय द्वारा सारा कामकाज रायसीना हिल्स स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक से संचालित हो रहा था लेकिन अब मंत्रालय ने कॉमन केन्द्रीय सचिवालय (सीएसएस) परिसर में शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों पहले ही नए कार्यालय में शिफ्ट हो गये हैं। महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टरा प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक, सीएसएस परिसर में राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आधारभूत ढाँचे को केन्द्रीकृत और आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। नया परिसर उन्नत सुविधाओं और बेहतर सुख्खा युक्त है, जो आधिकारिक कार्यों के लिए अधिक कुशल कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय की शिफ्टिंग का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस नए परिसर में कई मंत्रालयों को समायोजित कर अंतर-मंत्रालयी समन्वय बेहतर हो जाएगा।

51 हजार हो सकती है बेसिक सैलरी ! सहकारिता नीति अर्थतंत्र को करेगी मजबूत : शाह

○ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जल्द वेतनमान लागू करने का दावा

8वें वेतनमान लागू करने के लिए मैराथन बैठक



8वें वेतन आयोग के तहत 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी!

अनुमान है कि 8th Pay Commission के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगी। बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना बढ़ावती हो सकती है, जो एक्रोजेड फॉर्मूला के तहत चर्च में होगा। अगर ये फॉर्मूला 8वां वेतन आयोग के तहत भी यूज किया जाता है तो सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2।86 फिटमेंट के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये तक हो सकती है। वहीं पेंशन 9000 रुपये से बढ़कर 25740 रुपये हो जाएगी।

7वें वेतन आयोग पर भी लागू हुआ था ये फॉर्मूला

इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए 7वें वेतन आयोग 7th Pay Commission के तहत भी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया गया था। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई थी। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2।57 का फिक्स्ड फैक्टर लागू किया गया था। ये फिक्स्ड फैक्टर एक्रोयड फॉर्मूले से तय किया गया था।

सैलरी में ठीक वैसे ही इजाफा होगा, जैसे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने पर हुआ था। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा।

डॉ वॉलेस एक्रोयड ने यह फॉर्मूला पेश किया था, जिसे जीवन के न्यूनतम लागत तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस फॉर्मूले में यह बताया गया था कि एक्सेज कर्मचारियों की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। इस

फॉर्मूले को बनाते वक्त भोजन, कपड़ा और मकान जैसी कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ने 1957 में इस फॉर्मूले को अपनाया गया था।

अमेरिका ने भारत को सौंपे खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर, पाक सीमा के पास होगी तैनाती

हेलीकॉप्टरों की फीचर्स

4ई अपाचे को दुनिया के सबसे उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं।

थियार प्रणाली: हेलीकॉप्टर में हेलफायर मिसाइलें, रॉकेट और 30 मिमी प शॉलिल हैं, जो दुश्मन के टिकानों को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम हैं।

और नेविगेशन: रात में और प्रतिकूल मौसम में भी ऑपरेशन की क्षमता, जिस स्थिति में प्रभावी है।

तत्ता: अपाचे की डिजाइन इसे तेज और फुटीराल बनाती है, जो युद्धक्षेत्र में गति के लिए आदर्श है।

प्रणाली: यह हेलीकॉप्टर अन्य सैन्य इकाइयों के साथ समन्वय में बेहतरीन काम करता है।

वायुसेना के साथ संयुक्त अभियानों में भी एक बड़ी रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना पहले से ही दो स्क्वाड्रन अपाचे चला रही है- एक पठानकॉम में और दूसरा जैहलूर, असम में।

डिलीवरी में हुई देरी

इस डिलीवरी में देरी वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं और बदलते भू-जननीतिक हालातों के कारण हुई। ये हेलीकॉप्टर हई-जून

2024 तक भारत आने वाले थे लेकिन डिलीवरी में विलंब हो गया। इस हेलीकॉप्टरों की खरीद का समझौता वर्ष 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हुआ था, जिसकी कुल कीमत लगभग 600 मिलियन डॉलर (\$5,691 करोड़ रुपये) थी।

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2015 में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 22 अपाचे

हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए अलग समझौता किया था, जिसकी डिलीवरी 2020 के मध्य तक पूरी कर ली गई थी। इन नई अपाचे हेलीकाप्टरों की तैनाती के साथ भारतीय सेना की हमलावर शक्ति और समन्वित युद्ध क्षमता को नया बल मिलेगा, खासकर पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर। इन हेलीकाप्टरों को जोधपुर में तैनात करने का निर्णय सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जोधपुर, पश्चिमी सीमा के करीब होने के कारण, एक रणनीतिक स्थान है। यह भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट है, जहां सेना को तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अपाचे हेलीकाप्टरों की तैनाती से इस क्षेत्र में सेना की ऑपरेशनल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इन अत्याधुनिक हेलीकाप्टरों को यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस के विशाल एंटोनोव एन-124 रूसलान द्वारा अमेरिका के एरिजोना

से सीधे भारत के हिंडन एयर बेस पर लाया गया।

इस विमान पर "बी ब्रेव लाइक बुचा" लिखा हुआ था, जो यूक्रेन के बुचा शहर के साहस और प्रसिद्धि का प्रतीक है। एंटोनोव एन-124 दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, जो भारी और विशाल कार्गो को लंबी दूरी तक ले जाने में मश्रूम है।

एंटोनोव एन-124 पर लिखा "बी ब्रेव लाइक बुचा" नारा यूक्रेन के बुचा शहर की वीरता और रूसी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध को श्रद्धांजलि देता है। एंटोनोव एयरलाइंस ने अपनी विमान बेड़े को यूक्रेन के उन शहरों के नाम पर समर्पित किया है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रभावित हुए। यह नारा न केवल यूक्रेनी लोगों की बहादुरी को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर उनका एकजुटता और हृदय का प्रतीक भी है।



ज्योति कुमारी
उत्तर प्रदेश: सम्पन्न क्षेत्र वाशियो को सूचित किया जाता है विगत वर्ष को तहत इस वर्ष भी नागरिकों के उपलब्ध हैं बजरंग कुशुती एवं लम्बी कूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन दिनांक 29/07/2025 को किया गया है। जिसके आयोजक विपिन मिश्रा (भाजपा ,मंडल मंत्री), संचालक प्रभात खूबे (एक्सेलेट), संरक्षक अरविन्द वामा ,संजय तिवारी, संचालक शैलेन्द्र शुक्ल, अनुराग पटेल, रेफरी घनश्याम वर्मा, जितेंद्र मौर्य सदस्य अंकित मिश्रा,दीपक पाण्डेय,शिखम पाण्डेय (L.I.C), नवीन तिवारी, एजाज हुसैन,हेदर अली,अमित,अलोक मौर्य,कुलदीप ,लकी तिवारी,दीपक अग्रहरि,अमित तिवारी,राज विश्वकर्मा,वाहिद अली, त्रयम्भ सिंह,अंशु कसीधर,शिवांशु अग्रहरि।
मुम्बई:- लम्बी कूद प्रतियोगिता सुबह 09:00 से 11:00 बजे तक कुशुती प्रतियोगिता 11:30 से 2:30 बजे तक स्थान:- ग्राम गौहाना कला अथी बिल्डिंग मैटेरियल के सामने कालीमाता चौरा निकट गौहाना संचालित भवन नोट:- सभी प्रतिभागि खिलाड़ियों को उचित उपहार से सम्मानित किया जाएगा ।

A first-person perspective shot from inside a CT scanner. The person's feet are visible in the foreground, resting on the scanner bed. The circular gantry of the scanner is visible in the background, illuminated with a cool blue light. The scene is dimly lit, emphasizing the clinical and somewhat isolating environment of the procedure.

भी करवाना है। साथ ही कार्यरत स्टाफ का पुर्ण विवरण लें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले भी सीसीटीवी कैमरे उनके पीछी, होटल व धर्मशाला के मेन गेट और प्रांगण में लगे होने चाहिए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 30 दिन तक स्टोर रहनी चाहिए। साथ ही सीसीटीवी का डाटा क्लॉउड, स्टोरेज में सेव करें ताकि डीवीआरआर गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर भी डाटा सुरक्षित रखा जा सके। अग्निशमन वरुं दुरुस्त हालत में

राज्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए आदेश

इंद्रेश कुमार पांडे
उत्तर प्रदेश: प्रयागराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दयाशंकर मिश्र 'दयालु' अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात सर्किट हाउस के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्माण संबंधी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होमियोपैथी कॉलेज में स्मार्ट क्लास



बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने चिकित्सालयों के लिए आवश्यक

जमीन को जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराने जाने एवं उपलब्ध जमीन जो कि अभी तक विभाग के

नाम नहीं हुयी है, उसके नामांतरण की कार्यवाही शीघ्रता से कराए जाने के लिए कहा है। मंत्री ने होमियोपैथी

कॉलेज में कक्षाओं के संचालन में यदि पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है तो रिक्त पदों पर जब तक स्थायी नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है तब तक सविदा पर कार्यरत शिक्षकों के अनुबंध को बढ़ा दिया जाए और आवश्यकतानुसार अन्य शिक्षकों को भी सविदा पर नियुक्ति करने के लिए कहा है।

उन्होंने संस्थानों में उपलब्ध सभी संसाधनों का शत प्रतिशत उपयोग करते हुए उन्हें और बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जाने के लिए कहा है। मंत्री ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी कावड़ मांगों

पर नियमानुसार आवश्यक प्रबंध किए जाने के लिए कहा है। मंत्री ने बैठक में उपस्थित ट्रम्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से नकली दवाओं के विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार एवं अनुचित प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने एवं पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करने के लिए कहा है। इस अवसर पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



घनश्याम दास/उत्तर प्रदेश: पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विधायक राजीव गुंबर व महापौर ने भी सेवा कर धर्म कमा रहे हैं। सहारनपुर में मां काली भैरव नाथ मंशापूर्ण हनुमान शिव मंदिर समिति भरत विहार मल्हौपुर रोड सहारनपुर ने परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मंदिर के 19 वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर श्रावण मास में मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगर वासी धर्म प्रेमियों के साथ साथ पूर्व सांसद माननीय राघव लखनपाल शर्मा, महानगर महापौर माननीय डॉक्टर अजय कुमार व नगर विधायक माननीय राजीव गुंबर को सादर आमंत्रित किया गया। मंदिर प्रांगण में पूजन-अर्चन के पश्चात पूर्व सांसद ने भक्तिभाव से कन्यापूजन कराया व भोजन का भोग लगवाया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार और नगर विधायक राजीव गुंबर ने श्रद्धापूर्वक मंदिर में आये श्रद्धालुओं को अपने से हाथों भोजन खिलाकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मंदिर समिति भरत विहार द्वारा श्रावण मास में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से किया गया। इस शुभ अवसर पर नगर व क्षेत्रीय सैकड़ों लोगों ने प्रेम सहित भाग लेकर भंडारे का शुद्ध भोजन ग्रहण किया। मंदिर कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने वहाँ पर पधारे समस्त श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के शुभ अवसर पर समिति के संरक्षक अबेश कपिल, अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव राकेश कुमार शर्मा, उप सचिव प्रोफेड शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, ओडिटर अनुज कुमार जैन, संगठन मंत्री किशन लाल मल्होत्रा, प्रचार मंत्री भुवन चंद्र जोशी, सलिल साहू सदस्य, वीदीप कुमार जैन सदस्य, रकम सिंह सैनी सदस्य, संसार सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

छोटाउदेपुर जिले में सड़को की मरम्मत कार्य मिशन मोड में हुआ शुरू



खत्री रफाकत इंदरीशभाई
गुजरात: छोटाउदेपुर जिले में धूल भरे हालात के कारण दो मागों पर शुरू हुए पैच वर्क के कार्य। डुंगरवाट-जांबुघोड़ा रोड 12.4 किमी और पावीजेतपुर-कदवाल रोड 15.40 किमी पर मरम्मत कार्य जारी किया गया। छोटाउदेपुर जिले में सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) द्वारा सड़कों की मरम्मत कार्य मिशन मोड में शुरू कर दी गई है। भारी वर्षा के कारण खराब हुई सड़कों को सुधार कर यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही शुरू की गई है। जिले के वीरे के दौरान राज्य के मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ासमा और जिला प्रभारी सचिव प्रवीणभाई सोलंकी ने भी क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत, छोटाउदेपुर जिले के जांबुघोड़ा तालुका के डुंगरवाट-जांबुघोड़ा रोड (12.4 किमी) और पावीजेतपुर-कदवाल रोड (15.40 किमी) की हालत बेहद खराब होने के कारण, सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) द्वारा तत्काल पैचवर्क के कार्य शुरू किए गए हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को राहत मिल सके।

गोरखपुर स्कूल गेट से लापता छात्र लखनऊ में मिली

ओम प्रकाश
उत्तर प्रदेश: गोरखपुर स्कूल गेट से लापता छात्र मंगलवार की देर शाम लखनऊ में मिल गई घर वाले वालों के डांटने पर वह नाराज होकर घर से गई थी। भोजन के लिए एक दुकान पर 2 दिन से झाड़ू पोछा कर रही थी। बाजार गई चचरी बहन की नजर पड़ी तो वह साथ ले गई बुधवार की सुबह छात्र को शाहपुर पुलिस लेकर पहुंची कक्षा 5 में पढ़ने वाली 12 वर्ष किशोरी शुक्रवार को अपने पिता के साथ स्कूल गई थी। दोपहर में स्कूल बंद होने के बाद घर नहीं पहुंची थी इसी बीच मंगलवार की शाम लखनऊ में रहने वाली चचरी बहन अपने पति के साथ बाजार गई थी जहां पर दुकानदार पर छात्र झाड़ू लगाते हुए दिखाई वह भागने लगी मगर बहन और जीजा ने दौड़ाकर पकड़ लिया शाहपुर थाना पुलिस लखनऊ पहुंची और बुधवार की सुबह गोरखपुर ले आई छात्र ने बताया उसे मोबाइल देखने से रोका जाता था सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है।

वॉइस ऑफ मीडिया संस्था की मीटिंग कबीर मंदिर हॉल में आयोजित



खत्री रफाकत इंदरीशभाई
गुजरात: बोडेली के वॉइस ऑफ मीडिया संस्था की विशेष बैठक शहर के कबीर मंदिर हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में गुजरात के विभिन्न जिलों से पत्रकारों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हितों को लेकर संवाद स्थापित करना और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में मार्गदर्शन देना था। मुलाकात के दौरान पत्रकारों को उनके अधिकारों, कानूनी सुरक्षा और मीडिया क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, पत्रकारों के समर्थन में लीगल एडवाइस तथा आवश्यक मदद के लिए संस्था द्वारा जरूरी कदम उठाने की भूमिका तय की गई। इस अवसर पर कुछ नए सदस्यों को वॉइस ऑफ मीडिया संस्था से जोड़ा गया और उनका स्वागत भी किया गया। बैठक के बाद उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी ने सौहार्दपूर्ण माहौल में भाग लिया। वॉइस ऑफ मीडिया द्वारा आने वाले दिनों में भी ऐसी गतिविधियों को निरंतर जारी रखते हुए पत्रकारों को मजबूत और सशक्त बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया।

दभोई वडोदरा केलनपुर जांबा पुल एक तरफ से भारी वाहनों के लिए बंद

जयदीप कुमार
गुजरात: हाल ही में आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल के ढहने के बाद, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार की नौद खुली और उसने गुजरात के पुलों की वास्तविकता की जाँच की, जिसमें कई पुलों को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क निर्माण विभाग ने दभोई के चांदेड़ और ओरसांग के करनेट पुलों का निरीक्षण किया, लेकिन दभोई, वडोदरा जांबा नदी, केलनपुर के बीजों की वास्तविकता सामने आई। निरीक्षण के दौरान केलनपुर पुल घिसा हुआ



दिखाई दिया और स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी वाहनों के गुजरने पर इसकी पपड़ियाँ गिर

जाती हैं। पशुपालन में लगे लोगों से पता चला है कि पुल मोड़ ले चुका है, यानी नीचे की ओर दब रहा है, जिससे कभी भी संकट पैदा हो सकता है। सड़क निर्माण और पंचायत विभाग के अधिकारियों को केलनपुर के पुराने पुल का दौरा करना चाहिए और कोई बड़ी आपदा आने से पहले उचित कदम उठाने चाहिए। दभोई और वडोदरा के बीच केलनपुर नदी पर बना पुराना पुल लगभग 50 साल पुराना माना जाता है, ऐसे में सड़क निर्माण पंचायत के अधिकारियों को अपने ऐसी चैंबर छोड़कर केलनपुर पुल का निरीक्षण करना चाहिए।

आनंद पोलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की

राजपूत रणजीत
गुजरात: आनंद जिले में जी.जी. जसानी साहब, पुलिस अधीक्षक, आनंद के सुंदर निदेशों के अनुसार, एन.डी.पी.एस.ई. के मार्गदर्शन में एस.ओ.जी. शाखा के पी.इन्स. ए.जे. असारी और एस.ओ. चौधरी, पी.एस.ई. एस.ओ.जी. आनंद और एच.आर. प्रजाप्रति, पी.एस.ई. एस.ओ.जी. आनंद द्वारा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। विद्यानगर डाकघर में पंजीकृत, अधिनियम संख्या 11215037250368/2025 एनडीपीएस अधिनियम 8 (सी), 29 (सी), तकनीकी और मानव संसाधनों की मदद से, आरोपी



(1) देव आनंदभाई राय, 29, विश्वकुंज सोसाइटी, बुद्धदेव कॉलोनी, केरलीबाग, वडोदरा शहर में रहते हैं (2) आदिलबेग उर्फ रोली अबिदाली मिर्जा, 254, सहखरनगर, बेसिल स्कूल के

सामने, तंडलजा, वडोदरा शहर में रहते हैं, वर्तमान में डी-38, करभरी पार्क सोसाइटी, बीना नगर, वासना रोड, वडोदरा शहर में रहते हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है।

थाना कालावाली पुलिस ने हेरोइन तस्करी के दो मामलों में पेशी से गैरहाजिर आरोपी को किया काबू

महिपाल सिंह
हरियाणा: डबवाली पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कालावाली पुलिस ने नशा तस्करी के दो अभियोगों में वांछित असल स्पलावर व शस्त्र अधिनियम के मामले में अदालत की पेशी से गैरहाजिर होने वाले आरोपी हरमन सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गदरना जिला सिरसा को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। एक अन्य अभियोग में सीआईए स्टाफ कालावाली ने 6.25 ग्राम हेरोइन चिट्ठा सहित आरोपी शमशेर सिंह पुत्र नसीब सिंह निवासी गदरना को



काबू कर बंद जेल करवाया था। जो आरोपी हरमन सिंह इन दोनों अभियोगों में असल तस्करी था। शस्त्र अधिनियम के एक 3 साल पुराने मामले में भी आरोपी अवलत की पेशी से गैरहाजिर चल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इसी

तरह 07 साल पुराने मामले में पेशी से गैर हाजिर चल रहे एक अन्य आरोपी तरसेम सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गदरना को काबू किया गया है। काबू किए गए दोनों आरोपियों हरमन सिंह व तरसेम सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा।

सुरखेडा गांव में रास्ते पर फंसे ट्रक में मिली विदेशी शराब की बोतले



खत्री रफाकत इंदरीशभाई
गुजरात: रंगपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सुरखेडा गांव में रास्ते पर फंसी एक ट्रक के पास से विदेशी शराब से भरी एक आवशर जन्त की गई। इस आवशर में चोरी के इवदे से ले जाई जा रही कुल अनुमानित 24,08,000/- की विदेशी शराब पाई गई। साथ ही आवशर वाहन की कीमत 210,00,000/- आँकी गई। इस प्रकार कुल 214,08,000/- का माल जन्त

किया गया। यह कार्रवाई छोटाउदुर की स्थानीय अपराध शाखा (एल.सी.बी.) द्वारा अंजाम दी गई। वडोदरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री संदीपसिंह एवं छोटाउद?र जिले के पुलिस अधीक्षक श्री इम्तियाज शेख के मार्गदर्शन व निदेशों के तहत तेजी से उचित कार्रवाई की गई। अधिकारियों और स्टाफ के संयुक्त प्रयास और कार्यकुशलता के चलते यह सफलता जल्द ही प्राप्त हो सकी।

आनंद में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर, राहुल गांधी 26 जुलाई को रहेंगे उपस्थित

खत्री रफाकतथुसैन
गुजरात: आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत कांग्रेस पार्टी गुजरात में संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में 26 से 28 जुलाई तक आनंद में कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के पहले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वडोदरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 10 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहाँ से वे सीधे आनंद के लिए



रवाना होंगे। उनका आगमन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का विषय बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन की समीक्षा कर उसे और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि आने

वाले समय में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और "मिशन 2027" के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात

में भय, भूख, भ्रष्टाचार और कमीशन का शासन चल रहा है। भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और अब कांग्रेस इसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। सहकारी क्षेत्र और दूध संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी शिविर में चर्चा का केंद्र रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन क्षेत्रों में सदस्य अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी इन संगठनों के अधिकारियों और सदस्यों के साथ संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यह शिविर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ जनता से जुड़ने की एक अहम पहल माना जा रहा है।

चुनाव आयोग बनाम अदालत

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड ‘वैध दस्तावेज’ नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। बिहार में पुनरीक्षण का करीब १६ फौसदी काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के आग्रह को नकार दिया है, लिहाजा अब न्यायिक पीठ का फैसला अथवा उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, यह 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान सामने आ सकता है। सर्वोच्च अदालत या तो न्यायिक आदेश देती है अथवा निर्देश देती है, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। अब अदालत और आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी परस्पर मयादाएं हैं, लिहाजा अहम सवाल है कि क्या आयोग बनाम अदालत की स्थिति बन गई है? क्या शीर्ष अदालत भविष्य के मतदाता-सूची पुनरीक्षण के मंहेनजर आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को चुनाव आयोग को बाध्य कर सकती है? चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता की नागरिकता का पता लगाना भी उसका संवैधानिक अधिकार है। बेशक यह मुद्दा भी सर्वोच्च अदालत के सामने उठेगा, क्योंकि न्यायिक पीठ कहती रही है कि चुनाव आयोग की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। वह यह मंत्रालय का संवैधानिक ज़म्मेदेश है। लिहाजा मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में, बिहार में ही, जिन 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की संभावना आयोग ने जताई है, क्या उनकी नागरिकता भी सवालिया हो जाएगी? यह तय करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? आयोग ने अभी तक जो डाटा इक़ा किया है, उसके मंहेनजर आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में रेखांकित किया है कि बिहार की मतदाता सूचियों में करीब 18 लाख मृतकों के नाम दर्ज हैं, 26 लाख ऐसे नाम हैं, जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वहां के मतदाता हैं, 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दो-दो स्थानों पर हैं। इस तरह 52 लाख से अधिक नाम मतदाता-सूची से काटे जा सकते हैं।

बेशक ऐसे मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान अपील कर सकते हैं। क्या नागरिकता से जुड़े ऐसे मामले सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच सकते हैं? बिहार में चुनाव आयोग के पुनरीक्षण-अभियान का ज़रूरतस्त राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि विधानभभा में भेज-कुर्स्यां उछाली गई। मार्शल (सुरक्षार्कमी) और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ गए, धक्कामुक्की, हाथापाई बार-की नोबत आ गई। संसद परिसर में भी विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने बैनर, पोस्टर, तख्त्त्रायं लेकर संसद भवन के ढ़ामकर ढ़ारूढ पर विरोध-प्रदर्शन किया। संसद के भीतर विपक्षी सांसद अय्थ्थक के आसन तक ‘वेले’ में लाम-बंद हुए। नारेबाजी का शोर इतना था कि सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों की कार्यवाही दोनों दिन नहीं चल सकी। बेशक चुनाव आयोग के अभियान से लोकतंत्र की हत्त्त्वा की जा रही है अथवा नहीं, अलबत्त्ता लोकतंत्र लगातार ‘लहलुहान’ ज़रूर हो रहा है। अब सर्वोच्च अदालत को एक निश्चित फैसला सुना कर देश के लोकतंत्र को बचना है। अब तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है कि आयोग बंगाल में ऐसे 40 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट सकता है। सविधान के अनुच्छेद 324 और 32६ में चुनाव आयोग को पुनरीक्षण के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आयोग मतदाता-सूचियों में संशोधन कर सकता है। नाम काटे जा सकते हैं, तो नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाते हैं। चूँकि आजकल बांग्लादेशी घुसपैठियों, ग्न्प्यांगर की तरफ से रोहियां रसूलमामांनो की चर्चा खूब है। सरकारें अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज रही है। यदि आधार, राशन, वोटर कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज नकली, फर्जी बनाए जा रहे हैं, तो यह देश पर कलंक है। ऐसे कांठधारकों की छंटीनी होनी ही चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे माहील में सर्वोच्च अदालत का दायित्त्व ज़्यादा बड़ जाता है कि वह ऐसे छंटीनी को वैधता प्रदान करे।

परंपरा तभी पूजनीय, जब न्याय साथ हो

—सुधीर पाल—

छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा से लेकर झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों तक फैले आदिवासी समाज में उत्तराधिकार का अधिकार अब तक पुरुषों तक सीमित रहा है। ‘हमारी बहन बेटियां हमारी अमानत हैं, लेकिन जमीन पर उनका हक नहीं’, यह कथन कई आदिवासी समुदायों के सामाजिक ढांचे को दर्शाता है। पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में (जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि) आदिवासी समुदायों की परंपरागत व्यवस्थाओं को सम्मान देने की संवैधानिक व्यवस्था है। यह सविधान की धारा 13 और ३72 के तहत मान्यता प्राप्त ‘कस्टमरी लॉ’ के तहत आता है। परंतु जब ये परंपराएं लैंगिक भेदभाव पर आधारित होती हैं, तो वे सविधान की बुनियादी संरचना से टकरा जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन उन परंपराओं का नहीं जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। यह फैसला पहली दृष्टि में न्याय का प्रतीक लगता है, लेकिन जब हम गहराई में धूमक देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह न्याय है, या न्याय के नाम पर सामाजिक-सांस्कृतिक और कुछ हद तक पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र की विशिष्ट व्यवस्था में हस्तक्षेप?

भूमि अधिकार बनाम परंपरा

आदिवासी महिलाएं जंगल, जमीन और जल से गहराई से जुड़ी हैं। वह जल संग्रहण करती हैं, बीज बचाती हैं, खेती करती हैं, और जंगल को जीवित रखती हैं। फिर भी, जब भूमि के मालिकाना हक की बात आती है तो उसका नाम कहीं नहीं होता। अक्सर यह कहा जाता है कि आदिवासी समाज पुरुष प्रधान नहीं होता, वहां महिला को सम्मान मिलता है। लेकिन सम्मान और अधिकार में फर्क है। एक और तर्क दिया जाता है कि आदिवासी समुदायों में जमीन का स्वाभिमत सामुदायिक होता है ना कि व्यक्तिगत। लेकिन जमीन अधिग्रहण का मुआवजा का पैसा या आदिवासी जमीन की बिक्री का पैसा कभी किसी ग्राम सभा के खाते में जमा हुआ है? सामुदायिक स्वाभिमत के प्रकृति की जमीन जैसे पहनई, मुंडई, महतोई, डाली-कतारी, भूत-खेता, पन्थरा इत्यादि के अधिग्रहण की राशि ग्राम सभा के खाते में कभी जमा हुई है, इसके उदाहरण नहीं हैं। गैर आदिवासी पुरुषों से आदिवासी लड़कियों की शादी को भी जमीन से जोड़ कर देखा जाता है। मालूम हो जमीन की प्रकृति कभी नहीं बदलती है। आदिवासी महिला के गैर आदिवासी से शादी के बाद भी जमीन का नेचर आदिवासी ही रहेगा और हस्तांतरण नहीं हो सकता है। जैसे वनाधिकार कानून के तहत मिली जमीन की प्रकृति हमेशा वन भूमि की ही रहती है।

—क्या महिला को अपनी पुरैतनी जमीन बेचने, उस पर खेती करने, या गहराई में भूमि के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है?

—कई समुदायों में विवाह के बाद महिला अपने मायके की जमीन पर अधिकार नहीं रखती।

—क्या वह पुरानी परंपरा है या पितृसत्तात्मक कानूनों का धीरे-धीरे घुसपैठ?

यहां एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न उठता है-क्या पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है? पाँचवी अनुसूची, जो आदिवासियों की स्वायत्तता और परंपरा को मान्यता देता है, स्पष्ट करता है कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे केंद्र और राज्य के किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने से कस सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि जब कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब परंपरा या संस्कृति का हवाला नहीं दिया जा सकता। झारखंड के अधिवक्ता सुनील उरांव बताते हैं कि छोटानागपुर काव्त्तकारी अधिनियम, 1९०८, की धारा ६ (1) में उल्लेखित ‘भूमि जोतने वाला’ सिद्धांत का ऐसा अर्थ निकाला गया है कि विवाहित बेटियों को उनके पैतृक कृषि भूमि में अधिकार से वंचित किया गया।

—राजेश कुमार पासी—

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका को कहा था कि हम समझौता जरूर करेंगे लेकिन बिना किसी डेडलाइन के करेंगे।

उन्होंने कहा था कि इस तरीके से बातचीत की जाएगी तो हमें कोई ट्रेड डील नहीं करनी है। पहले अमेरिका ने 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी और अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।

अमेरिकी दबाव का नतीजा ये निकला है कि भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो शर्तें तय की थी, उनके अनुसार अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होने जा रही है बल्कि भारत का कहना है कि जैसे अमेरिका बात करेगा, उससे वैसे ही बात की जाएगी।

दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका की कई धमकियों के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं। जो समझौता हुआ ही नहीं, उसके कारण कैसे भारत पाकिस्तान अमेरिकी प्रभाव में खुद रोकने के लिए सहमत हो गए। जहां भारत का अमेरिका के साथ अभी तक व्यापार समझौता नहीं हो पाया है तो वहीं दूसरी तरफ तीन वर्षों की मेहनत के बाद ब्रिटेन के साथ भारत का समझौता होने जा रहा है। भारत इस समझौते के जरिये अमेरिका को संदेश दे रहा है कि वो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। इस समझौते के जरिये भारत ने सुनिश्चित किया है कि उसके १9 प्रतिशत निर्यात

—प्रियंका सौरभ—

मुंबई में वर्ष २००६ में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 1८९ लोगों की जान ली गई और लगभग ८०० से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी झ् न्याय की। परंतु जब लगभग 1१ वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गुंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सजा न मिल पाये का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे

—डॉ. शैलेश शुक्ला—

विश्व बैंक (२०२५): विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट (अप्रैल २०२५) में कहा गया है कि भारत, जो विश्व की 1४% आबादी का घर है, के पास केवल ४% जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे यह विश्व के सबसे अधिक जल-तनावग्रस्त देशों में से एक है। जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग २.2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल की पहुंच से वंचित हैं और ४.2 अरब लोगों को स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है। भारत में, नीति आयोग की २०१८ की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि २०३० तक देश के ४०% से अधिक हिस्से में गंभीर जल संकट हो सकता है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर पहले ही डे ज़ीरो की स्थिति का सामना कर चुके हैं, जहां जल स्रोत पूरी तरह सूख गए। यह आंकड़ा और भी भयावह है : भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1९५१ में ५,१७७ घन मीटर से घटकर २०२५ में केवल १,३४१ घन मीटर रह गई है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। जल संकट अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। इस संपादकीय में, हम जल संकट के कारणों, प्रभावों और टिकाऊ जल प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे, साथ ही भारत के संदर्भ में व्यावहारिक समाधानों का प्रस्ताव देंगे।

जल संकट के पीछे परस्पर जुड़े

ब्रिटेन के समझौते से किसको संदेश दे रहे मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की विदेश यात्रा पर हैं, जहां भारत ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है। २०२२ से इसके लिए भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत चल रही थी और अब इस समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। बेशक ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच होने जा रहा है लेकिन इस समझौते से मोदी पूरी दुनिया को एक संदेश देने जा रहे हैं। विशेष तौर पर मोदी इस समझौते के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है तब से डोनाल्ड ट्रंप यह राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के युद्ध विराम करवाया था। भारत सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से नकार दिये जाने के बावजूद उनका राग अलापना बंद नहीं हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड डील करने की बात कहकर मनाया था। सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्या बनाता है जिससे वो अमेरिका के साथ व्यापार करने जा रहा है।

दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका की कई धमकियों के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं। जो समझौता हुआ ही नहीं, उसके कारण कैसे भारत पाकिस्तान अमेरिकी प्रभाव में खुद रोकने के लिए सहमत हो गए। जहां भारत का अमेरिका के साथ अभी तक व्यापार समझौता नहीं हो पाया है तो वहीं दूसरी तरफ तीन वर्षों की मेहनत के बाद ब्रिटेन के साथ भारत का समझौता होने जा रहा है। भारत इस समझौते के जरिये अमेरिका को संदेश दे रहा है कि वो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। इस समझौते के जरिये भारत ने सुनिश्चित किया है कि उसके ११ प्रतिशत निर्यात

जब गुनहगार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं....

अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाजी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामों पर जमानत कराए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समग्र पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नजरअवाही और राजनीतिक चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दाेषियों को सजा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आंसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवनों की असुरक्षा हमारी हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सजा न मिल पाये का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे

उत्पादों को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी श्रेणी में रखा जाएगा। भारत पर अमेरिका द्वारा लगातार डेडलाइन देकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो किसी भी और अब इस समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। बेशक ये समझौता भारत ही अमेरिका के साथ समझौता करेगा।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका को कहा था कि हम समझौता जरूर करेंगे लेकिन बिना किसी डेडलाइन के करेंगे। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से बातचीत की जाएगी तो हमें कोई ट्रेड डील नहीं करनी है। पहले अमेरिका ने 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी और अब इसे बढ़ाकर ३१ जुलाई कर दिया गया है। अमेरिकी दबाव का नतीजा ये निकला है कि भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो शर्तें तय की थी, उनके अनुसार अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होने जा रही है बल्कि भारत का कहना है कि जैसे अमेरिका बात करेगा, उससे वैसे ही बात की जाएगी। भारत का अमेरिका को सीधा संदेश है कि वो किसी दबाव में व्यापार समझौता करने वाला नहीं है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील की बातचीत के दौरान ब्रिटेन के तीन प्रधानमंत्री बदल गए लेकिन बातचीत चलती रही। इससे यह भी संदेश जाता है कि ट्रेड डील किन्हीं दो लोगों के बीच नहीं होती बल्कि दो देशों के बीच होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्ट्रॉर्मर ने कहा है कि ब्रेजिट के बाद ये उनके देश की सबसे बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों को है। भारत में ५० लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है और मेक इन इंडिया को इससे फायदा होने की संभावना जताई जा रही है।

दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका की कई धमकियों के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं। जो समझौता हुआ ही नहीं, उसके कारण कैसे भारत पाकिस्तान अमेरिकी प्रभाव में खुद रोकने के लिए सहमत हो गए। जहां भारत का अमेरिका के साथ अभी तक व्यापार समझौता नहीं हो पाया है तो वहीं दूसरी तरफ तीन वर्षों की मेहनत के बाद ब्रिटेन के साथ भारत का समझौता होने जा रहा है। भारत इस समझौते के जरिये अमेरिका को संदेश दे रहा है कि वो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। इस समझौते के जरिये भारत ने सुनिश्चित किया है कि उसके ११ प्रतिशत निर्यात

अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाजी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामों पर जमानत कराए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समग्र पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नजरअवाही और राजनीतिक चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दाेषियों को सजा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आंसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवनों की असुरक्षा हमारी हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे झ जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुमक जना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह

भारत इससे यह संदेश दे रहा है कि अमेरिका भारत को कमजोर देश न समझे. हो सकता है कि उसकी दबाव बनाकर समझौता करने की रणनीति कुछ देशों के साथ सफल हो गई हो लेकिन भारत के मामले में ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका को समझना होगा कि उसकी भारत के साथ इस मामले की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। यहां तक कि कोई छोटी डील भी नहीं हो सकी है। अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति का ये परिणाम निकला है कि भारत ने कई ऐसे क्षेत्रों को बातचीत से बाहर निकाल दिया है जिन्हें पहले वो अमेरिका के लिए खोलने की बात करने वाला था। भारत दूसरे देशों को उन क्षेत्रों में आने के लिए भारत से अब उन क्षेत्रों के बारे में कोई बात नहीं होगी। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि बिना किसी दबाव के भी दूसरे देशों के साथ समझौता किया जा सकता है।

जहां तक भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले समझौते की बात है तो दोनों देशों ने इसके लिए चौदह दौर की बातचीत की है और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। मोदी जी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस समझौते का लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को २०३० तक दोगुना करके १२० अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। इस समझौते से भारत के वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं और अन्य कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन का बाजार शुन्य शुल्क या कम शुल्क में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा भारत के कामगारों और प्रोफेशनलों को ब्रिटेन में काम करने में आसानी होगी और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और

केवल छलावा होगा।
क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अपराधी बच निकले, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज्यादा उसे "दिखाने" पर जोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के दृष्टि से शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे झ जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुमक जना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह

भारत इससे यह संदेश दे रहा है कि अमेरिका भारत को कमजोर देश न समझे. हो सकता है कि उसकी दबाव बनाकर समझौता करने की रणनीति कुछ देशों के साथ सफल हो गई हो लेकिन भारत के मामले में ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका को समझना होगा कि उसकी भारत के साथ इस मामले की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। यहां तक कि कोई छोटी डील भी नहीं हो सकी है। अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति का ये परिणाम निकला है कि भारत ने कई ऐसे क्षेत्रों को बातचीत से बाहर निकाल दिया है जिन्हें पहले वो अमेरिका के लिए खोलने की बात करने वाला था। भारत दूसरे देशों को उन क्षेत्रों में आने के लिए भारत से अब उन क्षेत्रों के बारे में कोई बात नहीं होगी। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि बिना किसी दबाव के भी दूसरे देशों के साथ समझौता किया जा सकता है।

जहां तक भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले समझौते की बात है तो दोनों देशों ने इसके लिए चौदह दौर की बातचीत की है और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। मोदी जी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस समझौते का लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 20३0 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। इस समझौते से भारत के वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं और अन्य कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन का बाजार शुन्य शुल्क या कम शुल्क में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा भारत के कामगारों और प्रोफेशनलों को ब्रिटेन में काम करने में आसानी होगी और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और

उन्हें ब्रिटेन की पेंशन योजना के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।

ब्रिटेन को भी इस समझौते से बड़ा फायदा होने जा रहा है। ब्रिटेन के अल्कोहल और यात्री कारों को भारत के बाजार में जगह मिलेगी. इन्हें शुल्कमुक्त नहीं किया जा रहा है लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम शुल्क पर भारत में इनकी बिक्री हो सकेगी। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों मं ब्रिटिश सामानों को भारत में सस्ते में बेचा जा सकेगा। इससे ब्रिटिश सामान दूसरे देशों की तुलना में भारत में काफी सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन की विगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं लेकिन ब्रिटेन को यह भी समझ आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था खुद ही दूब रही है तो उसके साथ जुड़कर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि ब्रिटेन दूसरे देशों की तरफ देख रहा है। ब्रिटेन को चीन से भी बड़ी उम्मीद है लेकिन चीन की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है और चीन की अर्थव्यवस्था भी नीचे की ओर जा रही है। ऐसे हालात में ब्रिटेन भारत की अनदेखी नहीं कर सका है और उसका भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। भारत के लिए अब यूरोपियन यूनियन का रास्ता भी खुलने का रहा है।

पीएम मोदी इस समझौते के जरिये दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि अब भारत की वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं और अन्य कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन का बाजार शुन्य शुल्क या कम शुल्क में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा भारत के कामगारों और प्रोफेशनलों को ब्रिटेन में काम करने में आसानी होगी और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और

केवल छलावा होगा।
क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अपराधी बच निकले, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज्यादा उसे "दिखाने" पर जोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के दृष्टि से शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे झ जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुमक जना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह

यौन शोषण के आरोपी की क्लाइंट लिस्ट में ट्रम्प, उनकी शादी में भी हुआ था शामिल

एपस्टीन को बर्थडे पर नेकेड गर्ल की भेजी थी फोटोग्राफ

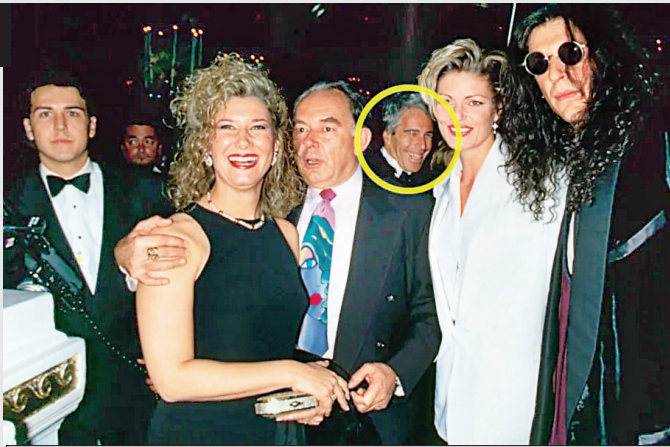
वॉशिंगटन / एजेंसी।

नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी जेफ्री एपस्टीन की फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट्स सीएनएन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अर्लीन जर्नरल पाम बॉन्डी ने खुद राष्ट्रपति ट्रम्प को मई महीने में इसकी जानकारी दी थी। हालांकि, क्लाइंट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यह कोई चौकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो दस्तावेज बॉन्डी ने राष्ट्रपति को दिखाए थे, उनमें ट्रम्प का नाम पहले से ही मौजूद था। इससे पहले बुधवार को ट्रम्प और एपस्टीन की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें से कुछ तस्वीर से पता चला कि एपस्टीन 1993 में ट्रम्प की दूसरी शादी में शामिल

हुआ था। यह खुलासा उस वक़्त हुआ है जब कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट छपी थी कि 2003 में ट्रम्प ने एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एक लड़की की न्यूड फोटो थी। हालांकि ट्रम्प ने इस चिट्ठी को लिखने की बात से इनकार किया है।

एपस्टीन की क्लाइंट लिस्ट में होने का मतलब क्या है: एपस्टीन की 'क्लाइंट लिस्ट' से मतलब उन लोगों की एक लिस्ट से है, जो उसके यौन शोषण और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। एपस्टीन पर यह आरोप लगे थे कि वह नाबालिग लड़कियों को लोगों तक पहुंचाता था और उनका शोषण करता था। एपस्टीन की 'क्लाइंट लिस्ट' इसलिए चर्चा में रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें कई बड़े और मशहूर लोगों के नाम हैं। जैसे राजनेता, अमीर कारोबारी, या दूसरी प्रभावशाली हस्तियां।



ट्रम्प ने फर्जी खबर कहकर खारिज किया

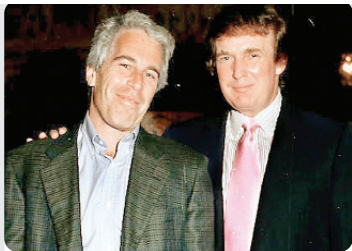
प्लाजा होटल में हुए इस इवेंट में एपस्टीन की मौजूदगी के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं थी। सीएनएनएन ने इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो, और फिर बार-बार इसे फर्जी बताकर फोन काट दिया। क्लाइंट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन वेडम ने इन खुलासों को खारिज करते हुए कहा – ये सिर्फ बिना सबूत के तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनका इस्तेमाल गलत नज़रिया बनाने के लिए किया जा रहा है।

कभी एपस्टीन के जिगरी दोस्त थे ट्रम्प

ट्रम्प और एपस्टीन की मुलाकात भी एक पार्टी में ही हुई थी। 2002 में ट्रम्प ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था – मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ, कमाल का आदमी है। हम दोनों को कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। यह बयान बाद में ट्रम्प के लिए मुसीबत बन गया। 1992 में ट्रम्प ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट में एपस्टीन और वीयरलीडर्स के साथ एक पार्टी की। 2019 में एनबीसी ने इसका एक फुटेज जारी किया था। जिसमें ट्रम्प, एपस्टीन को एक महिला की ओर इशारा करते दिखते हैं और झुककर कहते हैं– देखो वह बहुत हॉट है।

एपस्टीन के जेट से यात्रा करते थे ट्रम्प

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रम्प ने सात बार एपस्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक ट्रम्प ने ये सफर 1993 से 1997 के बीच किया था। हालांकि, ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच थीं। ट्रम्प ने कहा था कि उन्होंने कभी एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड का टूर नहीं किया और न ही कोई गलत काम किया।



ट्रम्प और एपस्टीन की दोस्ती में दरार

ट्रम्प- एपस्टीन की दोस्ती के बीच दरार 2004 में फ्लोरिडा के पाम बीच पर बनी प्रॉपर्टी हाउस ऑफ फ्रेंडशिप के कारण आई। यह संपत्ति नर्सिंग होम मैनेज एंड गोवर्नमेंट की थी, जो दिवालियापन की वजह से नीलामी हो रही थी। ट्रम्प-एपस्टीन दोनों इस 6 एकड़ की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे। ट्रम्प ने इसे अमेरिका में सबसे बेहतरीन जमीन बताया था। उनका इरादा इसे खरीदकर नए तरह से ट्रांसफॉर्म करना और फिर बेचने का था, जबकि एपस्टीन वहां रहना चाहता था। ट्रम्प ने टेलीफोन से हिस्सा लिया। एपस्टीन के और से तीन वकीलों ने बोली लगाई। ट्रम्प ने 356 करोड़ की बोली के साथ प्रॉपर्टी हासिल कर ली थी।

► शिव मंदिर को लेकर कंबोडिया-थाइलैंड के बीच ठनी

कंबोडियाई सैनिकों की फायरिंग में 12 थाई लोगों की हुई मौत

थाइलैंड सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, एफ-16 विमान तैनात किया

बैंकॉक/नोम पेन्ह / एजेंसी।

थाइलैंड और कंबोडिया के बीच गुरुवार सुबह सीमा पर गोलाबारी हुई है। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14 घायल हैं। थाइलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने सुबह गोलीबारी की, जबकि थाई सेना ने कहा कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन से हमला किया और फिर तोप और लंबी दूरी के बीएम 21 रॉकेटों से हमला किया। हमले को देखते हुए थाइलैंड ने बॉर्डर पर एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किया है। इस साल 28 मई को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट जारी है। इसी विवाद की वजह से इंडोनेशिया की पीएम पाइतोनतारन शिनवात्रा को भी पद से हटया गया था।

थाइलैंड ने 40 हजार नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया: हमले के बाद थाइलैंड ने सीमा से लगे 86 गांवों से लगभग 40 हजार नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। वहीं, कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह स्थित रॉयल थाइलैंड दूतावास ने कहा कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना के कारण, दूतावास ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा है।



क्या है शिव मंदिर विवाद

दोनों बौद्ध देशों की सीमा पर स्थित ग्रीह विहार मंदिर है। दरअसल, यह एक 1000 वर्ष प्राचीन हिन्दू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे शिव मंदिर भी कहते हैं और यह यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में 800 सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में हुआ था। हालांकि, इसका जटिल इतिहास 9वीं शताब्दी से जुड़ा है। मंदिर का निर्माण ख्मेर साम्राज्य के राजा यशोवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और बाद में अन्य राजाओं द्वारा इसे पूरा किया गया।

यूनेस्को के कदम से तनाव और गहराया

इस मंदिर पर थाइलैंड शुरू से ही अपना दावा करता रहा है। 1959 में कंबोडिया इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा, जहां तीन सालों तक ये मामला चला, फिर 1962 में कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया गया। थाइलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला तो मान लिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर अड़ गया और वहां की करीब 4.6 वर्ग किमी जमीन पर अपना कब्जा ठोक दिया। यह विवाद 2008 में तब और गहरा गया, जब हथशस्त्र ने इस ऐतिहासिक मंदिर को अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया।

रेणुकास्वामी मर्डर :कर्नाटक हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फटकारा

दर्शन को बेल देने पर कहा,कोर्ट ने पावर का गलत इस्तेमाल किया

नई दिल्ली /

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को कन्नड़ एक्टर दर्शन श्रुगुदीपा को बेल देने के फैसले पर दूसरी बार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट ने रेणुकास्वामी मर्डर में ज्यूडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इससे पहले 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से एक्टर दर्शन को मिली बेल पर सवाल उठाए थे। इस दौरान कहा था कि लगता है हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर की बेल रद्द करने का फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, एक्टर दर्शन को रेणुकास्वामी मर्डर केस में 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो जेल से रिहा हुए थे।

हाईकोर्ट जज से ऐसी गलती स्वीकार्य नहीं

जरिस्ट जेबी पारदीवाला और जरिस्ट आर महादेवन की बेल ने गुरुवार को कहा- वे हाईकोर्ट वाली गलती नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्य आरोपी पवित्रा गोड़ा के वकील से कहा- हम दोषसिद्धि या बरी करने का कोई फैसला नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के जमानत आदेश की भाषा पर भी नाराजगी जताई।

अमरनाथ का हिमलिंग पिघला

3.50 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

जम्मू / एजेंसी।

इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में तीन लाख पचास हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने महज 22 दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हिमलिंग की ऊंचाई यात्रा शुरू होने से पहले लगभग बाईस फीट थी, जो मौसम की वजह से जल्दी पिघल गया।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने गुफा में लोहे की ग्रिल लगाना, हेलीकॉप्टर को 5 किमी दूर उतारना जैसे संरक्षण उपाय किए।श्रद्धा की शक्ति को न हिम पिघला सकता है और न ही मौसम की मार इसे नष्ट कर सकती है। इसका प्रमाण है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, जिसमें महज 21 दिनों में ही 3.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके



हैं, भले ही इस बार हिमलिंग यात्रा शुरू होने के सिर्फ 8 दिन बाद ही पूरी तरह पिघल गया हो।यात्रा प्रारंभ होने से पहले हिमलिंग की ऊंचाई लगभग 22 फीट थी। लेकिन मौसम की अनिश्चितताओं के चलते वह जल्दी ही विलीन हो गया।बावजूद इसके हिमलिंग को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख पाना संभव नहीं हो सका। पहले ही पिघला, फिर भी आस्था की यात्रा रुकी नहीं।

एयर इंडिया विमान हादसे में इकलौते बचे विश्वास कुमार अभी तक सदमे में

पिता बोले, बेटा रात-रातभर नहीं सोता, चिंता में उसकी मां भी बीमार

अहमदाबाद / एजेंसी।

अहमदाबाद विमान हादसे को डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन कई पीड़ित परिवार अभी भी 270 लोगों की जान लेने वाली इस त्रासदी के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। कुछ ऐसा ही हाल विमान हादसे में इकलौते बचे शख्स विश्वास कुमार भालिया का है, जिन्होंने हादसे में अपने भाई अजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। विश्वास अब तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं।

उनके परिवार का कहना है कि विश्वास को नींद नहीं आती। रात-रातभर जागते रहते हैं। इस वजह से उसका एक छोटे बच्चे की तरह हर समय ध्यान रखना पड़ रहा है। परिवार के अलावा दोस्त भी लगातार उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।



पिता बोले-विश्वास को मानसिक आघात पहुंचा

मीडिया ने विश्वास के पिता रमेशभाई भालिया से फोन पर बात की तो उन्होंने भी बेटे की हालत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बेटा विश्वास अपने कमरे तक ही सीमित होकर रह गया है। वह ज्यादातर समय वहीं बिताता है। उसे मानसिक आघात पहुंचा है, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी आंखों से किनारा भयावह दृश्य देखा था। उन्होंने बताया, हादसे में सगे भाई की भी मौत हो गई।

मालदीव के राष्ट्रपति के साले के विवादित बोल

अब्दुल्लाह ने मोदी को इस्लाम का दुश्मन बताया

माले / एजेंसी।

मालदीव के अखबार अधाधु की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल्लाह ने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां वे 26 जुलाई को होने वाले मालदीव के

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। शेख अब्दुल्लाह ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा था- मोदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वे आतंकवादी हैं। उन्होंने बाकरी मस्जिद गिराई है, पुरानी मुस्लिम जमीनों को लूटा और अहमदाबाद को कब्रिस्तान में बदल दिया। उन्हें मालदीव बुलाना बड़ी गलती है।

मणिपुर में छह महीने और बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली, आरएनएन। मणिपुर में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया है। 13 अगस्त से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब जनवरी 2026 तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। बता दें कि राज्य में 13 फरवरी 2024 से राष्ट्रपति शासन लागू है और संविधान के मुताबिक हर 6 महीने में इसकी संसद से मंजूरी लेनी होती है। मौजूदा मंजूरी 13 अगस्त को खत्म हो रही थी जिससे अब बढ़ाया गया है।

आज का इतिहास

- 1689: फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1722: फादर्स रेली वॉर मेन और मैसाचुसेट्स सीमा के साथ आरम्भ हुआ।
- 1759: युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने फ्रांस से फोर्ट नीग्रारा पर कब्जा कर लिया।
- 1813: भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता (अब कोलकाता) में आयोजित हुई।
- 1837: इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफ तलापूर्वक प्रदर्शन किया गया।
- 1854: वाल्टर हंट को पहले पेपर शट कॉपर का अमेरिकी पेटेंट हासिल हुआ।
- 1893: कॉरिथ नहर को औपचारिक रूप से खोला गया था।

तकनीक

यह एयरोबाइक डीजल से भी उड़ेगी, टॉप स्पीड: 200किमी/घंटा, स्लैंडर से 4 गुना हल्की

दुनिया की पहली एयरबाइक, कीमत है 7 करोड़

वारसा / एजेंसी।

पोलैंड की कंपनी वोलोन्ट ने एक नई एयरबाइक बनाई है, जो 200किमी/घंटा की स्पीड से हवा में उड़ सकती है। खास बात ये है कि इसे 4 तरह के फ्यूल से उड़ाया जा सकता है। इसमें डीजल, बायोडीजल, जेट-ए1 और केरोसिन शामिल है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें टेक-ऑफ और लैंडिंग दिखाई गई है। एयरबाइक को टॉमस्ज पाटन ने बनाया है, जो जेटसन वन जैसी इलेक्ट्रिक फ्लाईंग मशीन बना चुके हैं। उनका कहना है कि ये एकदम रियल वर्ल्ड स्पीड बाइक है, जो हवा में तेजी से उड़ सकती है और कहीं भी मूव कर सकती है।

1 अगस्त से बुकिंग शुरू होगी: एयर बाइक की कीमत 8.80 लाख डॉलर (लगभग 7.37 करोड़ रुपये) है। इसकी सिर्फ कुछ ही यूनिट्स बनाई जाएंगी। एयरबाइक को 1 अगस्त 2025 से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट (टोलोनाट.कॉम) से बुक किया जा सकेगा।



फ्लाईंग बाइक की खास बातें

ये सिंगल-सीटर फ्लाईंग बाइक है, जो फिल्मों की स्पीड बाइक जैसी दिखती है। इसकी बॉडी कार्बन फाइबर की है और इसे 3डी प्रिंटिंग के जरिए बनाया है। इससे ये हौरो स्लैंडर बाइक (120किमी) के मुकाबले 4 गुना हल्की है। इसका वजन सिर्फ 30किलो है और 95किलो तक का वजन उठा सकती है। इस पर राइडर को 360-डिग्री ओपन व्यू मिलता है। जिससे राइडिंग का अलग एक्सपीरियंस मिलता है।

फ्लाइट कंप्यूटर और स्टेबलाइजेशन सिस्टम से कंट्रोलिंग

इसमें जेट टराइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें घूमने वाले प्रोपेलर्स नहीं हैं, जो इसे युनिक बनाता है। जेट टराइन एक तरह का इंजन होता है, जो हवा को तेजी से खींचकर और बाहर निकालकर एयरबाइक को हवा में उड़ने की ताकत देता है। ये आमतौर पर हवाई जहाजों में इस्तेमाल होता है। कंपनी का कहना है कि ये 200किमी/घंटा की टॉप स्पीड से उड़ सकती है, लेकिन अमेरिका में इसे एफएए अल्ट्रालाइट नियमों की वजह से 102किमी/घंटा की स्पीड से उड़ाया जा सकेगा।

भारत में 3 कंपनियां बना रहीं

- **शून्य पहली 6 सीटर फ्लाईंग टैक्सी, 160 किमी मैक्सिमम रेंज:** एयरोसेप्स स्टार्टअप सरला एविएशन एयर टैक्सी शून्य पर काम कर रही है। कंपनी इसका प्रोटोटाइप मॉडल इस जनवरी में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश कर चुकी है।
- **महिंद्रा अगले साल लाएगी पहली एयर टैक्सी:** ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चैयर्समैन आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट में कंफर्म किया था कि 2026 तक भारत को उसकी पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मिल जाएगी।
- **हाइब्रिड फ्लाईंग कार घर की छत से भी उड़ सकेगी:** भारत में चेन्नई स्थित विनाटा एयरोमोबिलिटी कंपनी हाइब्रिड फ्लाईंग कार बना रही है।

कॉर्पोरेट जॉब छोड़ खेती में कमाल कर रही एमबीए पास छोरी

नईदिल्ली, एजेंसी। आज के समय खेती एक जबरदस्त प्रॉफिट वाला बिजनेस बनता जा रहा है। काफी लोग अपनी मोटी सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर खेती कर रहे हैं और जॉब से ज्यादा कमा रहे हैं। इन्हीं में एक नाम छत्तीसगढ़ की स्मृति चंद्राकर का भी शामिल है। स्मृति ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर पारिवारिक खेती शुरू की। आज उनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये का है। साथ ही वह अपने खेतों में 125 लोगों को रोजगार



भी दे रही हैं। स्मृति कहती हैं, %कौन कहता है कि खेती में फायदा नहीं होता? लोग सोचते हैं कि ये छोटा काम है और इसमें कमाई नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है।% स्मृति छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक किसान परिवार में पली-बढ़ी। उनका बचपन अपने पिता और दादा के साथ हे-भरे धान के खेतों में बीता, जहां उन्होंने जीवन और खेती के बारे में अपने पहले सबक सीखे।

5 साल तक की कॉर्पोरेट नौकरी- स्मृति ने रायपुर में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वह पुणे चली गई और वहां से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद उन्होंने पुणे में पांच साल तक एक कंपनी में जॉब की। बाद में उन्होंने अपने परिवार के करीब रहने के लिए रायपुर जाने का फैसला किया।

सर्ज प्राइसिंग के चक्कर में वसूल रहा था अनाप-शनाप किराया

हैदराबाद एजेंसी। आप महानगर या बड़े शहरों में रहते हैं और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो इस घटना से आप भी दो-चार हुए होंगे। आपसे कभी बेस फेयर के नाम पर तो कभी सर्ज प्राइसिंग के नाम पर अनाप-शनाप किराया वसूला जाता होगा। हैदराबाद के एक 27 साल के आदमी ने ऐसा



ही कुछ झेला था, लेकिन उसने कोर्ट का रुख किया और बाइक टैक्सी कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन- ने कंपनी को गलत तरीके से व्यापार करने का दोषी पाया। कंपनी एक ही दूरी के लिए अलग-अलग किराया ले रही थी।

कौन है मुकदमा जीतने वाला- उपभोक्ता फोरम में यह मामला के. राजेश ने दायर किया था। वह शहर में आने-जाने के लिए अक्सर बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। राजेश ने कंपनी के ऐप में एक अजीब चीज देखा। बीते 20 जून को, उन्होंने नल्लाकूटा से हिमायतनगर के लिए एक राइड बुक की। यह दूरी 2.14 किलोमीटर थी और उनसे 32 रुपये लिए गए। लेकिन, 4 जुलाई को, उन्होंने सिर्फ 300 मीटर की दूरी के लिए राइड बुक की और उनसे फिर से 32 रुपये लिए गए।

उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया- बाइक टैक्सी की इस तरह की किराया नीति के खिलाफ राजेश ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन- , जिसे आम भाषा में उपभोक्ता फोरम कहते हैं, में वाद दायर किया।

क्रिप्टो मार्केट ने पहली बार छुआ चार ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा

ट्रंप सरकार की नीतियों से मिली रफ्तार



नईदिल्ली, एजेंसी। क्रिप्टो सेक्टर का बाजार मूल्य शुक्रवार को लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। क्रिप्टोकॉरेसी डेटा एग्ग्रीगेटर कोइनगेको के जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह आंकड़ा क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक मिल का पथर है। प्रमुख बाजारों में नियामकीय स्पष्टता, निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी और संस्थागत निवेश के मजबूत प्रवाह ने इस उद्योग को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है।

अमेरिका ला रहा क्रिप्टो के लिए नियम- अमेरिकी हाउस ऑफ रीप्रेसेंटेटिव ने गुरुवार को

अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टोकॉरेसी टोकन के लिए एक नियामक ढांचा बनाने के लिए विधेयक पारित किया। इस क्रिप्टोकॉरेसी को स्ट्रेबलकॉइन के रूप में जाना जाता है। फिलहाल विधेयक को राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेज दिया गया है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा। हार्गव्य लैसडाउन के इक्रिटी रिसर्च प्रमुख डेरेन नाथन ने कहा कि ट्रंप की नीति आने के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद सांसद अब भी कुछ हद तक सतर्कता बरत रहे हैं।

मखाना टॉप सुपरफूड के रूप में उभरा, बदलती पसंदों से फूड इंडस्ट्री के लिए नए अवसर

नईदिल्ली, एजेंसी। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारतीय सुपरफूड मखाना ने उपभोक्ताओं के बीच खास जगह बना ली है। फार्मली की %हेल्दी स्नैकिंग रिपोर्ट 2025% के अनुसार 65 प्रतिशत उपभोक्ता प्रतिभागियों ने मखाने को अपनी पहली पसंद बताया है।

55 प्रतिशत उपभोक्ताओं को प्रिजर्वेटिव-मुक्त विकल्पों की तलाश- रिपोर्ट में हेल्थी स्नैक्स की ओर मजबूत बदलाव की भी चर्चा की गई है। 55 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता अब सक्रिय रूप से प्रिजर्वेटिव-मुक्त विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा, आधे से ज्यादा लगभग 52 प्रतिशत ऐसे स्नैक्स को प्राथमिकता देते

हैं, जो दोबारा सील होने वाली, पर्यावरण- अनुकूल पैकेजिंग में आते हैं। यह पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

स्वादयुक्त सूखे मेवे का चलन- सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ताओं के बीच सुविधा एक प्रमुख कारक बनी हुई है। लगभग 45 प्रतिशत उपभोक्ता बार और सूखे मेवे आधारित मिठाइयों जैसे चलते-फिरते नाश्ते को पसंद करते हैं। नमकीन विकल्पों में मखाना और स्वादयुक्त सूखे मेवे स्पष्ट रूप से पसंदीदा हैं। इससे बाजार में स्वस्थ नाश्ते के विकल्पों की एक नई लहर चल पड़ी है।

इन रूझानों से यह संकेत मिलता है कि उपभोक्ता अब सेहत पर केंद्रित,



टिकाऊ और सुविधाजनक स्नैक विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बदलाव उन ब्रांडों के लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है, जो बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उत्पाद पेश कर रहे हैं।

सुपर-स्नैक में परिवर्तन- रिपोर्ट

के अनुसार, मखाना और स्वादयुक्त सूखे मेवे पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरे हैं। 36 प्रतिशत उपभोक्ता उत्तरदाताओं ने भुने हुए और स्वादयुक्त सूखे मेवों को सबसे पसंदीदा नमकीन नाश्ते के रूप में पसंद किया। वहीं 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से

15851 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी धोखाधड़ी का खुलासा, पकड़ी गई 3558 फर्जी कंपनियां



नईदिल्ली, एजेंसी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 15,851 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 29 फीसदी अधिक है। हालांकि, इस अवधि में फर्जी कंपनियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तिमाही में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने कुल 3,558 फर्जी कंपनियों का पता लगाया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह संख्या 3,840 थी। अधिकारियों ने बताया कि हर महीने औसतन 1,200 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया गया। यह गिरावट संकेत देती है कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चलाया गया अभियान असरदार साबित हो रहा है। इस तिमाही में की गई कार्रवाई के दौरान 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 659 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही में 26 गिरफ्तारियां हुई थीं और 549 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी।

ऐसे हुई करोड़ों की धोखाधड़ी- जीएसटी व्यवस्था के तहत, कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर चुकाए गए टैक्स को आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकती हैं। लेकिन फर्जी कंपनियां सिर्फ इस टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है।

मखाना को चुना, जो आधुनिक समय के सुपर-स्नैक में इस परिवर्तन को दर्शाता है।

मखाना बोर्ड का गठन- यह बढ़ती लोकप्रियता भारत सरकार द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की हाल की घोषणा के अनुरूप है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य राज्य के प्रमुख मखाना उद्योग को बढ़ावा देना है।

चिप्स और वेफर्स की लोकप्रियता बरकरार- हालांकि नए प्रारूप लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन चिप्स और वेफर्स जैसे पारंपरिक विकल्प अभी भी बरकरार हैं। 14 प्रतिशत लोग इन्हें चुनते हैं, इसके बाद 10 प्रतिशत

नमकीन और 9 प्रतिशत लोग खाद्या जैसे मल्टीग्रेन स्नैक्स चुनते हैं। मिठे स्नैक्स भी विकसित हो रहे हैं, जबकि चॉकलेट भारत में हमेशा से पसंदीदा रहा है।। मूगफली का मक्खन, हेजलनट और पिस्ता जैसे मेवे अब स्वाद और स्वास्थ्य के मिश्रण के कारण पसंद किए जा रहे हैं।

ब्रांड लॉयल्टी, जो पहले पारंपरिक बड़ी कंपनियों तक सीमित थी, अब कई प्लेटफॉर्म पर फैल रही है। जहां एक ओर ऑफलाइन स्टोर अब भी योजनाबद्ध खरीदारी और खोज का प्रमुख जरिया बने हुए हैं, वहीं क्रिक कॉमर्स और इन्फ्लुएंसर-चालित कंटेंट की बढ़ती महारत और आचानक स्नैकिंग आदतों में तेजी आई है।

भारतीय चाय की मांग दुनिया में बढ़ी, एफताय25 में 26 करोड़ किलोग्राम का हुआ निर्यात

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत के चाय निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत से चाय निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.85 प्रतिशत बढ़ा। देश का चाय निर्यात 250.73 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 257.88 मिलियन किलोग्राम (लगभग 26 करोड़ किलोग्राम) हो गया है।

चाय निर्यात का मूल्य 290.97 रुपये पहुंचा- वहीं प्रति किलोग्राम चाय निर्यात का मूल्य बढ़कर 290.97 रुपये हो गया। यह वित्त वर्ष 2024 के 258.30 रुपये से 12.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।



चाय निर्यात में लगातार हो रही वृद्धि- कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, चाय निर्यात की मात्रा 256.17 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई। यह जनवरी से दिसंबर 2023 की पिछली अवधि से 10.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उत्तर भारत से निर्यात में हुई 8.15 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त वर्ष 2025 के दौरान उत्तर भारत से निर्यात की मात्रा 161.20 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई। यह वित्त वर्ष 2024 के 149.05 मिलियन किलोग्राम से 8.15 प्रतिशत की वृद्धि की दर्शाता है। इसी प्रकार, दक्षिण भारत से निर्यात 2025 में 4.92 प्रतिशत घटकर 96.68 मिलियन किलोग्राम रह गया। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में 101.68 मिलियन किलोग्राम था।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 40 अरब डॉलर पार, जाने अश्विनी वैष्णव हैदराबाद में और क्या बोले

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें पिछले 11 वर्षों के दौरान आठ गुना वृद्धि हुई है। वहीं, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह बात कही।

आईआईटी हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की तीव्र प्रगति पर भी जोर दिया, जिसके अगस्त या सितंबर 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। भविष्य की ओर देखते हुए, वैष्णव ने कहा कि पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, व्यावसायिक स्तर पर, इसी वर्ष बन जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के शीर्ष पांच सेमीकंडक्टर देशों में से एक बनने की राह पर है, और उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों और सामग्रियों पर बढ़ते ध्यान पर भी चर्चा की।

केंद्रीय रेल, सूचना व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, महज 11 वर्षों में, हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को छह गुना बढ़ा दिया है। यह दोहरे अंकों की छक्कड़ है जिससे कोई भी कॉर्पोरेट ईर्ष्या करेगा। हमने अपने निर्यात को आठ गुना बढ़ाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 40 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को पार कर लिया है, जो विकास



की एक अभूतपूर्व गति है, जो हमारे जैसे बहुत कम देशों ने देखी है।

उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिया और कहा कि केवल साढ़े तीन वर्षों में, भारत एक संपूर्ण 4वें दूरसंचार स्टेक डिजाइन कर सका। आज, यह लगभग 90,000 दूरसंचार टावरों पर स्थापित है, जो दुनिया के कई देशों के नेटवर्क से भी ज्यादा है।

आईटी मंत्री ने कहा कि दूरसंचार पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने 100 5जी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जहां छत्र 5जी उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों पर काम करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत की

विकास गाथा और अगली पीढ़ी के लिए आधार के पांच उदाहरण दिए- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, एआई, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार क्षेत्र और रेलवे।

उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए केंद्र ने लगभग 270 कॉलेजों और संस्थानों को कैड्रेस, सिनोप्सिस और सीमेंस के नवीनतम ईडीए उपकरण दिए हैं और यदि स्टार्टअप को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 340 हो जाती है। वैष्णव ने कहा, दुनिया में कहीं भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रतिभा विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के पास इस समय बड़े भारत का तीसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है, जिसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है।

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से होगा लागू, बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और चार देशों के यूरोपीय समूह ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जबकि स्विस् घड़ियों, चॉकलेट और कटे और पॉलिश किए गए हिरों जैसे कई उत्पादों को कम या शून्य शुल्क पर अनुमति दी गई है।

गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत-ईएफटीए टीईपीए 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। समूह ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है - समझौते के कार्यान्वयन के बाद 10 वर्षों के भीतर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अगले पांच वर्षों में 50



बिलियन अमेरिकी डॉलर- जिससे भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह भारत द्वारा अब तक हस्ताक्षरित किसी भी व्यापार समझौते में सहमत अपनी तरह की पहली प्रतिज्ञा है।

यह प्रतिबद्धता इस समझौते का मुख्य तत्व है, जिसे पूरा होने में लगभग 16 वर्ष लगे, जिसके बदले में भारत ने श्वस्रञ्ज देशों

से आने वाले कई उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए। इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड है। ऐसे तीन देशों के साथ भारत का व्यापार कम है।

इस समझौते में भारत अपनी टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों का 82.7 प्रतिशत हिस्सा देने की पेशकश कर रहा है, जो

ईएफटीए निर्यात का 95.3 प्रतिशत है, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक आयात सोना है। घरेलू ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले स्विस् उत्पाद, जैसे घड़ियां, चॉकलेट, बिस्कुट और घड़ियां, कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा।

सेवा क्षेत्र में, वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारत ने ईएफटीए को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जैसे लेखांकन, व्यावसायिक सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं, वितरण और स्वास्थ्य। दूसरी ओर, देश ने स्विट्जरलैंड से 128 उप-क्षेत्रों में, नॉर्वे से 114, लिक्टेनस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। जिन क्षेत्रों में भारतीय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, उनमें कानूनी, दूर्य-श्रव्य, अनुसंधान एवं विकास, कंस्यूटर, लेखांकन और लेखा परीक्षा शामिल हैं।

2025 की पहली छमाही में भारत में 108 आईपीओ से 4.6 अरब जुटाए गए; सौदों में 30 प्रतिशत गिरावट के बावजूद लचीलापन कायम

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गतिविधियों ने साल 2025 की पहली छमाही में मजबूती दिखाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कुल 108 सौदे हुए, जिनसे 4.6 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई गई। भारतीय आर्थिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) वह प्रक्रिया है जिससे सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। रिपोर्ट में बताया गया कि सौदों की संख्या में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसके बावजूद यह बाजार के लचीलेपन को दर्शाता है। हालांकि, फंडरेजिंग में केवल 2 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो बाजार की स्थिरता को दर्शाता है। वैश्विक आईपीओ बाजार के आय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि- रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में, वैश्विक आईपीओ बाजार ने 539 सौदे दर्ज किए, जिससे 61.4 अरब डॉलर की राशि जुटाई गई।



वैश्विक अनिश्चितता और भू-

राजनीतिक तनाव का पड़ा असर

श्रद्धा की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रवृत्ति जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों के अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसमें कंपनियां अनुकूल बाजार समय और मूल्यांकन रणनीतियों को प्राथमिकता दे रही हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के कारण कई प्रमुख कंपनियों ने अपनी लिस्टिंग को स्थगित कर दिया है या मूल्यांकन पर पुनर्विचार किया है।

दूसरी छमाही में बेहतार

प्रदर्शन की उम्मीद

इसमें कहा गया कि बाजार सहभागियों को 2025 की दूसरी छमाही में बेहतार प्रदर्शन की उम्मीद है। यह स्थिर बाजार के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से सहायक सरकारी पहलों से प्रेरित होगा। घरेलू आर्थिक सुधार से आईपीओ बाजार में तेजी की संभावना है क्योंकि निवेशक भावना मजबूत हो रही है और बाजार में अस्थिरता कम हो रही है।



बॉर्डर 2 की शूटिंग को लेकर उत्साहित दिखे सुनील शेटी के बेटे अहान

सुनील शेटी के बेटे अहान शेटी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। अभी इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बताया है कि पुणे में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अहान शेटी वरुण धवन और दिलीपत दोसांझ के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं।

अहान ने पुणे में पूरी की शूटिंग

शुक्रवार को अहान शेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि उन्होंने पुणे में अपनी शूटिंग कंसीट कर ली है। अहान ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके कैप्शन में लिखा है और क्या है यह बॉर्डर? बस एक फौजी और उसके भाई हैं। पुणे में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ अब अगले कार्यक्रम पर चलते हैं।

वरुण धवन ने अहान के साथ चाय पी

इससे एक दिन पहले वरुण धवन ने भी बताया था कि पुणे में उन्होंने एनडीए की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अहान शेटी के साथ चाय और बिस्कुट खा रहे थे। वीडियो विलफ शेयर करते हुए वरुण धवन ने लिखा बॉर्डर 2 चाय और बिस्कुट। एनडीए में शूटिंग पूरी हो गई है। हमने बिस्कुट के साथ सेलेब्रेट किया है। पिता की तरह बनना चाहते हैं अहान कुछ दिनों पहले अहान शेटी ने बॉर्डर 2 से जुड़ने के अपने सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा वह अपने पिता की तरह बनना चाहते थे जो बॉर्डर (1997) में नजर आए थे। उन्होंने अपने पिता और अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा हर बेटा कहीं न कहीं अपने बाप जैसा बनना चाहता है। बॉर्डर 2 - 23 जनवरी 2026।

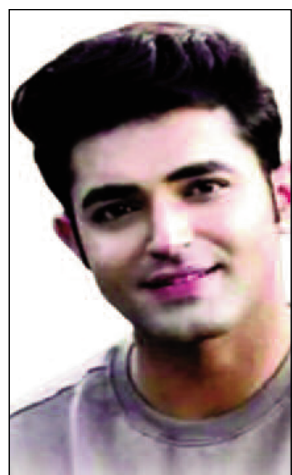
फिल्म के बारे में

आपको बता दें कि बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। फिल्म में भारतीय सेना की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता हैं। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।



बींदणी में मेरा किरदार बाहर से सख्त और अंदर से नर्म दिल वाला है

आगामी टीवी शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी - बींदणी में एक्टर आकाश जग्गा शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा शो के मेकर्स ने की। वह सीरियल में लीड किरदार निभाते नजर आएंगे। वह कुंदन नाम के लड़के का किरदार निभाएंगे, जो अंदर से बहुत भावुक है, लेकिन बाहर से सख्त दिखाई देता है। प्रथाओं की ओढ़े चुनरी - बींदणी एक महिला के अपने अस्तित्व को खोजने और साहस के साथ संघर्ष करने की कहानी है। शो का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए आकाश जग्गा ने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे सन नियो चैनल के शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी- बींदणी में लीड रोल मिला है। कुंदन का किरदार बहुत ही गहराई वाला है, उसमें कई भावनात्मक परतें हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह मैं इस किरदार से जुड़ाव महसूस करता हूँ, उसी तरह दर्शक भी इससे जुड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब लेखक और प्रोड्यूसर रघुवीर शेखावत सर ने मुझसे कहा, तुम्हें इस रोल को निभाने में मजा आएगा, इसमें बहुत कुछ करने को है, उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई।



शिल्पा शेटी का मॉलीवुड में काम ना करने की वजह का खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेटी को कन्नड़ मूवी केडी - द डेविल में देखा जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि मलयालम सिनेमा की फैन होने के बावजूद उन्होंने कभी इसमें काम क्यों नहीं किया! उन्होंने केडी.. के टीजर लॉन्च के मौके पर अपनी हिचकिचाहट के बारे में खुलासा किया। शिल्पा शेटी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने खुलासा किया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर्स के कई ऑफर्स भी मिले। शिल्पा ने कहा, मैंने कभी उन्हें हां नहीं कहा, क्योंकि मैं डरी हुई थी।

मलयालम सिनेमा से है प्यार

शिल्पा ने बताया कि मलयालम सिनेमा के लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। उन्होंने कहा, मुझे मलयालम सिनेमा बहुत पसंद है और मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये इंडस्ट्री भावनाओं को कैसे पेश करती है। उन्होंने ये भी बताया कि मलयालम फिल्मों में कहानी और एक्टिंग एक अलग ही लेवल पर होते हैं। उन्होंने

आगे कहा, मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगी तो अपने किरदार के साथ न्याय कर पाऊंगी। लेकिन देखते हैं, शायद मैं एक दिन कोई मलयालम फिल्म करूंगी।

मोहनलाल संग करना चाहती हैं काम

जब शिल्पा से पूछा गया कि क्या मलयालम इंडस्ट्री में कोई एक्टर है, जिसके साथ वो काम करना चाहेंगी तो उन्होंने मोहनलाल का नाम लिया। उन्होंने कहा, वो शानदार हैं। इतने साल बाद भी वैसे ही दिखते हैं। वो इंडियन सिनेमा के सबसे अमेजिंग एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पसंदीदा फिल्म नोवकेशाधूरथु कन्नुम नड्डू है।

फिल्म की कास्ट

केडी - द डेविल की बात करें तो इसका निर्देशन प्रेम कर रहे हैं। ध्रुव सरजा की एक्शन से भरपूर इस फिल्म में संजय दत्त, रेशमा नानेया, वी रविचंद्रन और रमेश अरविंद भी हैं।

मैंने धुरंधर जैसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी



अभिनेता अर्जुन रामपाल अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने फिल्म के फर्स्ट लुक को मिल रही प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह फिल्म उनकी अब तक की किसी भी फिल्म से बिल्कुल अलग है। अभिनेता ने कहा कि ऐसी फिल्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। अर्जुन ने कहा, फिल्म को बनाने से पहले मेकर्स ने काफी रिसर्च किया है। इसे बेहद अलग अंदाज में बनाया गया है। फिल्म की पूरी टीम ने

अपने-अपने काम में पूरी मेहनत की है। फिल्म के फर्स्ट लुक को मिल रही प्रतिक्रिया को देखने के बाद मैंने निर्देशक आदित्य धर को गले लगा लिया। फिल्म में अर्जुन के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में हैं। अर्जुन ने इस फिल्म में एक ग्रे किरदार निभाया है। ग्रे किरदार उन्हें कहते हैं जो पूरी तरह से अच्छे या बुरे नहीं होते। उनमें दोनों तरह के गुण शामिल होते हैं। अर्जुन ने कहा, फिल्म में मेरे किरदार में थोड़ा गुस्सा और सही-गलत का मिलाजुला भाव होगा, जो दर्शकों के लिए बिलकुल नया और अनोखा होगा। धुरंधर फिल्म को आदित्य धर ने न सिर्फ निर्देशित किया है, बल्कि इसकी कहानी को लिखा भी है। यही नहीं, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया है।

यादगार नहीं रहा शनाया का डेब्यू, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी 'आंखों की गुस्ताखियां'

स्टारकिड शनाया कपूर का बॉलीवुड डेब्यू वैसा नहीं रहा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उनकी डेब्यू फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' शुरुआती तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 30 लाख रुपये से अपना खाता खोलने वाली 'आंखों की गुस्ताखियां' बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती दिख रही है। फिल्म को वीकेंड का भी कोई लाभ नहीं मिला और शनिवार को जहां फिल्म ने सिर्फ 49 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं सप्ते को छुट्टी वाले दिन फिल्म की कमाई एक बार फिर घट गई। रविवार को अपने तीसरे दिन फिल्म सिर्फ 41 लाख ही जुटा पाई। इस तरह से शुरुआती तीन दिनों में 'आंखों की गुस्ताखियां' का कुल कलेक्शन सिर्फ 1.2 करोड़ रुपये ही हो पाया है। 'आंखों की गुस्ताखियां' का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार राव की 'मालिक' और हॉलीवुड फिल्म 'सुपरमैन' से है। 'आंखों की गुस्ताखियां' की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक भी दिन करोड़ में कमाई नहीं कर पाई है।



ऋषभ शेटी के साथ सम्राट कृष्णदेवराय पर फिल्म बनाएंगे आशुतोष गोवारिकर

फिल्म कांतारा से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाले ऋषभ शेटी ने एक रोमांचक फिल्म साइन की है। खबरों के अनुसार वे बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता-निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के साथ काम करेंगे। यह फिल्म व्यापक स्तर पर बनाई जाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष गोवारिकर और ऋषभ शेटी विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय पर फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म के जरिए सम्राट कृष्णदेवराय के जीवन की झलक को परदे पर दिखाएंगे। यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण एनटीआर बायोपिक, जयललिता बायोपिक और कपिल देव बायोपिक बनाने वाले प्रसिद्ध टॉलीवुड निर्माता विष्णु वर्धन इंदुरी करेंगे।

साउथ और बॉलीवुड के सितारे बनेंगे फिल्म का हिस्सा

आशुतोष गोवारिकर को लगान, स्वदेश और जोधा अकबर जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने मोहनजोदड़ो और पानीपत जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए भी जाना जाता है। वह श्री कृष्णदेवराय की बायोपिक को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए उत्साहित हैं। इस फिल्म में कई दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड सितारे अहम किरदार अदा करते दिखेंगे।

इन फिल्मों में नजर आएंगे ऋषभ शेटी

इस फिल्म को लेकर अभी और अपडेट सामने आना बाकी है। बात करें ऋषभ शेटी की तो वे फिल्म कांतारा 2 की तैयारियों में व्यस्त हैं। फिल्म कांतारा साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म का निर्देशन भी खुद ऋषभ शेटी ने किया। इसके अलावा ऋषभ फिल्म जय हनुमान में भी नजर आएंगे। फिल्म जय हनुमान का निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं।



जहराक बनकर स्क्रीन पर तबाही मचाएंगे करण वीर मेहरा

बॉलीवुड में जब भी किसी खतरनाक विलेन की बात होती है तो दर्शक कुछ डरावना देखने की उम्मीद करते हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए करण वीर मेहरा अपनी नई फिल्म में विलेन की भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। जी हां, उनकी आने वाली फिल्म 'सिला' में उनके खलनायक अवतार 'जहराक' की पहली झलक सामने आई है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

सिला में विलेन की भूमिका

निर्देशक ओमंग कुमार, जो 'मेरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी सशक्त फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अब 'सिला' नाम की एक रोमांटिक-एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में लीड रोल में हर्षवर्धन राणे और सादिया खतीब दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो है करण वीर मेहरा का खतरनाक और आक्रामक विलेन लुक। करणरी ने अपने इस लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जो अब फैंस को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही ये ऐसा लुक है जिससे करणवीर बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। जब इसफ भी खुद और सजा भी!

करण वीर ने सोशल मीडिया पर अपना लुक शेयर करते हुए लिखा - खुद ही खुदा, खुद ही इंसाफ! करणवीर की इस एक लाइन ने फैंस को उनके किरदार की गहराई और भयावहता का अंदाजा दे दिया है। पोस्टर में करण वीर लहलुहान शरीर, लंबे उलझे बालों और हाथ में तलवार लिए युद्ध के लिए तैयार दिख रहे हैं। उनकी आंखों की आग और शरीर पर खून के धब्बों ने उन्हें एक वरुण योद्धा के रूप में दिखाया है।

कहानी में ट्विस्ट लाने आ रहा है जहराक करण वीर का किरदार 'जहराक' फिल्म में काफी 'खतरनाक', 'इंटेंस' और 'डरावना' बताया जा रहा है। उनके लुक पर कई फैंस ने भी कमेंट किया है। उनके फैंस को लुक पसंद आया है। कई लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की कहानी समीर जोशी ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स आरंभ एम. सिंह ने तैयार किए हैं। संगीत की जिम्मेदारी अकिंत तिवारी, सचेत-परंपरा, श्रेयस पुराणिक और एलेक्सिया एवलिन जैसे प्रतिभाशाली संगीतकारों के पास है। ये टीम पहले ही कई हिट गाने दे चुकी है, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।

तीन चीजों पर काम कर रही हैं करिश्मा तन्ना

करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है वह तीन चीजों पर काम कर रही है। अपने ऊपर, अपनी जिंदगी पर और अपने सुकून पर। करिश्मा तन्ना की तस्वीरों को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है आपकी खूबसूरती का तोड़ नहीं। एक और यूजर ने लिखा है खूबसूरती की असली परिभाषा। करिश्मा तन्ना ने साल 2001 में टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अभिनय करियर की शुरुआत की। वह साल 2021 में बॉलीवुड फिल्म लाहौर कॉन्फिडेंशियल में नजर आई थीं। वह बाल वीर, एफआईआर और नागिन 3 जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं।

